(1) 4/70

**बिहार सरकार**
**उद्योग विभाग।**

संचिका संख्या– **SIPB2306000543**

## प्रेस नोट

मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्रा० लि०, अरावन, बेन, नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 960 MTPD क्षमता का पार–बॉईल्ड राईस उत्पादन इकाई की स्थापना करने हेतु 8818.00 लाख (अठासी करोड़ अठारह लाख रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 185 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

M-336

2

68/70

**बिहार सरकार**
**उद्योग विभाग।**

संचिका संख्या– **SIPB2106000185**

प्रेस नोट

मेसर्स ई एस ई एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, कुदरा, कैमूर में ग्रेन बेस्ड 60 KLPD इथेनॉल प्लान्ट एवं 2.0 मेगावाट को–जेनेरेशन पॉवर प्लान्ट इकाई की स्थापना हेतु कुल 7345.00 लाख (तिहत्तर करोड़ पैतालीस लाख रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 93 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

336

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>प्रेस नोट</u>

(3)

भारत सरकार पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के साथ अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य 1839 किलोमीटर की लम्बाई में छः राज्यों में क्षेत्र के आर्थिक एवं रोजगार क्षमता का आकलन करना है। विशेष रूप से विनिर्माण, कृषि संस्करण, सेवाओं और निर्यातोन्मुख इकाईयों में निवेश को प्रोत्साहित करना तथा समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वर्तमान आर्थिक एवं रोजगार क्षमता को विकसित करना है।

आई०एम०सी०, गयाजी के लिए पानी की उपलब्धता का आकलन एन०आई०सी०डी०सी० के द्वारा भूमि पर प्रस्तावित उद्योगों के प्रकार एवं प्रारंभिक मास्टर प्लान के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 8.5 एम०एल०डी० (मिलियन लीटर/दिन) एवं अल्टीमेटेड डिमांड 19.00 एम०एल०डी० है। अल्टीमेटेड डिमांड के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 8.5 एम०सी०एम० (मिलियन घन मीटर) पानी की आवश्कता है।

आई०एम०सी०, डोभी (गयाजी) फेज–02 के तहत बियाडा द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली 1300 एकड़ भूमि में से प्लॉट नं०–174 एवं 175 के सन्निकट जल संसाधन विभाग को जलाशय निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त स्थल पर 19 एम०एल०डी० जल उपलब्धता हेतु 8.5 एम०सी०एम० भंडारण क्षमता का जलाशय निर्माण के लिए क्षेत्रीय अभियंता द्वारा आवश्यक लगभग 324 एकड़ भूमि हेतु बियाडा, पटना को संसूचित किया गया है।

लीलाजन नदी वर्षा आधारित नदी है, जिसमें मॉनसून के दरम्यान ही पानी प्रवाहित होती है। घोड़ाघाट के समीप लीलाजन नदी के बायीं ओर से लीलाजन सिंचाई योजना निःसृत है। लीलाजन मुख्य नहर एक अर्देन नहर है, जिसे लाईनिंग कर इसके रूपांकित जलश्राव 18 क्यूमेक को आवश्यकतानुसार 2.5 क्यूमेक तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि नदी से 40 दिनों तक जल लेने से 8.5 एम०सी०एम० क्षमता के जलाशय में एक वर्ष के लिए पानी संचय किया जाना है।

योजना को 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

# बिहार सरकार
## पंचायती राज विभाग

## प्रेस – नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant मद की राशि की विमुक्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात सौ सैंतालीस करोड़ संतानवे लाख चौंसठ हजार रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी।

(मनोज कुमार)
सचिव

(21) (5)

# बिहार सरकार
## वित्त विभाग

## प्रेस नोट

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि दिनांक–31.03.2025 को समाप्त हो गई है। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अब तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि समाप्त होने एवं सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए अनुदान राशि का हस्तांतरण संभव नहीं हो पायेगा तथा अनुदान राशि प्राप्त नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित होंगी।

अतः इन कारणों से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, जो वित्तीय वर्ष 2021–25 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अनुरूप राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

22.4.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

**बिहार सरकार**

**विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

संचिका संख्या– वि॰ प्रा॰ एवं त॰शि॰वि॰ (VII) योजना –04/2024

06/70

6

## प्रेस नोट

बिहार काउंसिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत कुल–94 पदों में से कुल 87 पद को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के कुल–53 (तिरेपन) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे बिहार काउंसिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना का अनुश्रवण एवं उसके संचालन सफलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से किया जा सकेगा, जिससे विज्ञान में अभिरूचि रखने वाले छात्र/छात्राएं, पर्यटक तथा आम जन लाभान्वित होगें।

हस्ताक्षर :–

नाम :– लोकेश कुमार सिंह

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

6/70

**बिहार सरकार**

**विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

**संचिका संख्या– वि०प्रा०(I) मु०स्था०–03/2026**

7

## प्रेस नोट

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) के चयन संबंधी नीति– 2026 पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के कार्यान्वयन से विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा इससे संबद्ध संस्थानों में प्रतिभाशाली यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं अन्य कार्यों के संपादन में इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

**हस्ताक्षर :–**

नाम :– लोकेश कुमार सिंह
पदनाम :– सचिव
विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

# प्रेस–नोट

राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा को तथा आसूचना तंत्र को और विकसित किये जाने के दृष्टिकोण से विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक, बॉर्डर (IG, Border) के पदनाम से 01 (एक) नये पद का सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अनिल चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

(9)

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

*प्रेस नोट*

अरवल जिलान्तर्गत अंचल–करपी, मौजा–झिकटिया, थाना सं0–227, खाता सं0–61, खेसरा सं0–51 की कुल प्रस्तावित रकवा–06.81 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भवन निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

10



# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

*प्रेस नोट*

औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल—देव के विभिन्न मौजा, खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा—13.09 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, देव के निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

(11)

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

### *प्रेस नोट*

सहरसा जिलान्तर्गत अंचल–सलखुआ के मौजा–कबीरा, थाना सं0–255, खाता सं0–1025, खेसरा सं0–522 कुल प्रस्तावित रकवा–06.61 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर मुख्यमंत्री विकास योजना अन्तर्गत आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

12

# बिहार सरकार
## सिविल विमानन विभाग

## प्रेस नोट

बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन–स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी–बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के रूप में अधिकतम बारह माह हेतु ₹10,40,00,000/–(दस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया से बैंकॉक (थाईलैंड) के मध्य सीधी हवाई संपर्कता स्थापित होने से बिहार में विदेशी पर्यटकों, विशेषकर बौद्ध पर्यटकों के आगमन में सुविधा एवं वृद्धि होगी। थाईलैंड से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु भारत आते हैं, जिनमें बिहार के बोधगया सहित अन्य बौद्ध स्थलों का विशेष महत्व है। इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने से बौद्ध पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा।

पर्यटकों के आगमन में वृद्धि से होटल, परिवहन, आतिथ्य, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार एवं अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास के साथ–साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के अवसर भी उत्पन्न होंगे। यह संपर्कता बिहार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में सहायक होगी।

(डॉ0 निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

13

# बिहार सरकार
# गृह विभाग
# (आरक्षी शाखा)

## प्रेस–नोट

वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्य बाल (STF) में विशिष्ट दक्षता प्राप्त एवं आसूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल तथा पूर्वानुभव के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने एवं उक्त हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

(अनिल चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
बिहार, पटना।